विदेश नीति : नये आयाम

रहीस सिंह

ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बल्कि भारत की कूटनीतिक क्षमता बढ़ाने का भी काम करेगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही वर्ष में कई महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री ने फोर्टालिजा (ब्राजील) में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया जहाँ उन्होंने ब्रिक्स देशों के लिए आगे रोडमैप बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात की। यहीं भारत नए ब्रिक्स बैंक का पहला अध्यक्ष भी घोषित हुआ

किसी देश की विदेश नीति अथवा दुनिया के दूसरे देशों के साथ उनके संबंधों तथा उनसे हासिल उपलब्धियां-अनुपलब्धियां एक सीमित समय सीमा में बांधी नहीं जा सकतीं। ऐसे में आकलन करते समय कई छोटे-छोटे बिंदु छूटे रह जाते हैं। यद्यपि वे महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन उनके परिणाम तात्कालिक की बजाय दीर्घकालिक परम्परा का हिस्सा होते हैं। इसलिए विदेश नीति की जो उपलब्धियां दिखती हैं कभी-कभी उनका परिमाण और विस्तार उससे कहीं बहुत अधिक होता है या फिर कम। हम इसी सामान्य मान्यता के आधार पर यह देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कितना कूटनीतिक लाभांश अर्जित किया और एक राष्ट्र के लिए उनका महत्व क्या है।

श्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब ही भावी विदेश नीति के प्रारूप तथा परिवर्तन का संकेत मिल गया था। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने 8 पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाकर 'नेबर्स फर्स्ट' का राजनयिक मास्टर स्ट्रोक प्रयुक्त किया था। इस ओथ डिप्लोमैसी में हामिद करजई (अफगानिस्तान), प्रधानमंत्री तोबगे (भूटान), राष्ट्रपति यामीन (मालदीव), प्रधानमंत्री कोइराला (नेपाल), प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (पाकिस्तान) और राष्ट्रपति राजपक्षे (श्रीलंका) ने एक मजबूत कूटनीतिक बॉण्ड बनाने का संकेत भी दिया था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को नयी ऊर्जा देने की रणनीति पर काम किया। अपनी विदेश यात्राओं के माध्यम से पहले पड़ोसियों को जोड़ने और फिर बाहरी दुनिया के साथ नए कूटनीतिक बॉण्डों का निर्माण करने की कोशिश की। इस दिशा में पहला कदम प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के रूप में देखा गया। यहीं से 'बी 4 बी' यानि भूटान के लिए भारत और भारत के लिए भूटान की एक नयी शुरूआत हुई जिसने भारत-भूटान संबंधों में पहले उत्पन्न हुए कुछ छोटे-मोटे जख्मों को भरने का काम किया। भारत-श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने मार्च 2015 में श्रीलंका का दौरा किया। इससे एक महीने पहले मैथ्रीपाला सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली यात्रा के तौर पर भारत आये थे। इसके बाद विदेश मंत्री नेपाल गयीं जहां 23 साल बाद भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुयी और फिर 17 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा इस हिमालयी देश की पहली यात्रा की गयी।

नेपाल के बाद पूरब के साथ संबंधों की समृद्ध म्यांमार मैट्रिक्स से शुरू हुई। इस दौरान भूमि, समुद्र एवं हवाई संयोजकता का प्रयास हुआ। इसके बाद भारत का रुख पी 5 की ओर हुआ जिसकी शुरुआत चीन से हुई। चीन के बाद भारत के प्रति उदासीन दिखने वाले रूस के उप-प्रधानमंत्री दमित्रि ओ रोगोजिन का भारत आगमन हुआ और इसके बाद फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस का जो प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति ओलांद का निमंत्रण लेकर आए थे। इसके बाद सुषमा स्वराज और केरी ने पांचवीं भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सामरिक वार्ता की अध्यक्षता की तथा भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वाशिंगटन जाने का न्योता भी मिला।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भारतीय विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था एवं इतिहास विषय से संबंधित 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पिछले तीन दशकों से आर्थिक एवं वैदेशिक विषयों पर स्तंभ लेखन एवं संपादन। ईमेल: raheessingh@gmail.com

ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बल्कि भारत की कूटनीतिक क्षमता बढ़ाने का भी काम करेगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही वर्ष में कई महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री ने फोर्टालिजा (ब्राजील) में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया जहाँ उन्होंने ब्रिक्स देशों के लिए आगे रोडमैप बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात की। यहीं भारत नए ब्रिक्स बैंक का पहला अध्यक्ष भी घोषित हुआ। ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान ही लातिन अमेरिका के नेताओं से बात हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत एवं मर्कासुर व्यापार ब्लॉक तथा चिली के बीच तरजीही व्यापार करार का उपयोग अधिक कारगर ढंग से किए जाने की बात रखी। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ ने छठवीं ब्रिक्स शिखर बैठक में अतिरिक्त समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा, नवीकरण ऊर्जा तथा साइबर के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के अलावा निवेश एवं व्यापार प्रवाह बढ़ाने का निर्णय किया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने गुयाना के राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोतार तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति देसी बाउटर्से के समक्ष इस बात को रखा कि दक्षिण अमेरिका के इन देशों में भारतीय मूल के लोगों-जो सदियों पहले आकर यहां बस गये हैं-ने भारत तथा दक्षिण अमेरिका के देशों के बीच मैत्री के मजबूत सेतु के रूप में काम करना जारी रखा है।

मार्च 2015 में प्रधानमंत्री का तीन देशों, सेशेल्स, मॉरिशस और श्रीलंका का दौरा हिंद महासागर पर केंद्रित था। यह महासागरीय कूटनीति (ओसियन डिप्लोमैसी) की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम था जो एक तरह से भारत के ब्लू वाटर पालिसी की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री बाराकुडा समारोह में शामिल हुए जो भारत-मॉरीशस सहयोग की निशानी के तौर पर स्वीकार किया जाता है। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री ने फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का दौरा किया। यह यात्रा यूरोपीय देशों और कनाडा के साथ सहयोग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। फ्रांस में परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में ठोस प्रगति सहित रिकार्ड 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। जर्मनी में प्रधानमंत्री और चांसलर मर्केल ने संयुक्त रूप से हनोवर मैस्से (मेले) का उद्घाटन किया और भारत व्यापार को यूरोपीय व्यापारिक अधिकेंद्र से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ा। कनाडा में आर्थिक संबंधों, ऊर्जा और यहां तक कि सांस्कृतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित था। कनाडा की उनकी यात्रा ऐतिहासिक थी क्योंकि यह 42 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कनाडा यात्रा थी।

प्रधानमंत्री के जापान दौरे के साथ भारत के सन्निकट पड़ोस के साथ विदेश एवं आर्थिक नीतियों का अनुरेखण नए ढंग से हुआ और 'तपते सूरज-उगते सूरज' के बीच संबंधों का नया बॉण्ड बना। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी समय जापान ने भारत में अगले पांच वर्षों में 3.5 ट्रिलियन येन के सार्वजनिक एवं निजी निवेश तथा वित्तपोषण का वचन दिया। अगला कदम सिंगापुर में विदेश मंत्री द्वारा भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 'भारत का वर्ष' के उद्घाटन का रहा। भारत में संयोजकता एवं निवेश की परियोजनाओं, विशेष रूप से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, चेन्नई-बंगलुरू औद्योगिक कॉरिडोर तथा पूर्वोत्तर भारत में इन परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए सिंगापुर की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रण आदि महत्वपूर्ण रहे। तत्पश्चात तेल क्षेत्र में वियतनाम के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत तथा रक्षा संबंधों को गहन करने का प्रयास किया गया।

श्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब ही भावी विदेश नीति के प्रारूप तथा परिवर्तन का संकेत मिल गया था। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने 8 पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाकर 'नेबर्स फर्स्ट' का राजनयिक मास्टर स्ट्रोक प्रयुक्त किया था। इस ओथ डिप्लोमैसी में हामिद करजई (अफगानिस्तान), प्रधानमंत्री तोबगे (भूटान), राष्ट्रपति यामीन (मालदीव), प्रधानमंत्री कोइराला (नेपाल), प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (पाकिस्तान) और राष्ट्रपति राजपक्षे (श्रीलंका) ने एक मजबूत कूटनीतिक बॉण्ड बनाने का संकेत भी दिया था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को नयी ऊर्जा देने की रणनीति पर काम किया।

पूरब के बाद मध्य-पूर्व के उन देशों के साथ संबंधों का नवीकरण करने का प्रयास हुआ। इस दिशा में शुरुआत तब हुई जब ओमान के विदेश मंत्री युसूफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला भारत आए। उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं रक्षा सहित विभिन्न द्विपक्षीय विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद युगांडा के विदेश मंत्री सैम कुटेसा भारत आए और दोनों देशों द्वारा व्यापक विकास सहयोग की संभावना को रेखांकित किया गया। इसके बाद नई दिल्ली में अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय की बैठक हुई और भारत की तरफ से अफ्रीकी देशों से द्विपक्षीय संबंधों की नयी शुरुआत करने की पहल का आग्रह किया गया।

अक्तूबर 2015 में प्रधानमंत्री अपनी बहुचर्चित अमेरिकी यात्रा के दौरान वैश्विक नेताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों से मिले लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव सिलिकन वैली रहा जहां से उन्होंने डिजिटल डिप्लोमैसी को मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त करने की कोशिश की। विशेष बात यह रही कि यहां 'पॉलिटिकल डिप्लोमैसी' 'डिजिटल डिप्लोमैसी (अथवा इकोनॉमिक डिप्लोमैसी) के सामने कमजोर पड़ती दिखी। यहां टोक्यो डिप्लोमैसी की पुनरावृत्ति भी दिखी जहां प्रधानमंत्री ने 'टच थेरेपी' का प्रयोग किया था। यह भारतीय नेतृत्व द्वारा दुनिया को नया संदेश था। यानि भारत विदेश नीति में रक्षा और सामरिक विषयों के सापेक्ष आर्थिक, विज्ञान व प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों को आगे रखकर कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता था।

इस बीच 2017 में अस्ताना (कजाकिस्तान) में भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का स्थायी सदस्य बना। वर्ष 2015 में उफा में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने का रास्ता साफ हुआ था जिस पर अंतिम मुहर 8-9 जून 2017 को अस्ताना में लगी। इस यूरेशियाई इकोनॉमिक जोन में प्रवेश पाने के अपने फायदे हैं। एससीओ पर गौर करते हुए यह देखना बेहद जरूरी है कि आखिर इसके

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, भारत, चीन, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका) के नेता

दो ध्रुवों के बीच का स्पेस कैसा है और भारत उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। सामान्यतौर पर आतंकवाद से लड़ने हेतु इस संगठन की अपनी कार्यपद्धति है। इस स्थिति में भारत एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की आतंकी नीतियों को प्रभावी ढंग से रख सकता है और उस पर दबाव बना सकता है। यही नहीं वह मध्य एशियाई संसाधनों से स्वयं को जोड़कर अपनी आर्थिक क्षमताओं का लाभ भी उठा सकता है। वह इस संगठन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, उज़बेकिस्तान और कजाकिस्तान का प्रयोग कर चाबाहर प्रोजेक्ट को यूरेशिया का प्रवेश द्वार बना सकता है। लेकिन क्या वास्तव में यह सब इतना आसान है।

इस शंका का सामधान भी तब हो गया जब भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में बनने वाले रणनीतिक चतुर्भुज (क्वैड) में शामिल हो गया। दरअसल चीन अपनी आर्थिक उन्नति के कारण एक क्षेत्रीय ताकत बन चुका है और अब वह साम्राज्यिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था इसलिए यह क्षेत्र सामरिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी बन गया। ऐसे में इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में सामरिक गठबंधन अपेक्षित एवं अपरिहार्य से प्रतीत होते हैं। ऐसे गठबंधनों की आवश्यकता प्रशांत क्षेत्र में भले ही अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया की हो लेकिन हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत को भी ऐसी जरूरत है। यही वजह है कि श्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, जनवरी 2015 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा हुई तो दोनों देशों ने एशिया-प्रशांत और हिन्द महासागर क्षेत्र पर एक संयुक्त विज़न दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज में भारत औपचारिक रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति का साझीदार बन गया और उसने अपनी 'एक्ट एशिया नीति' को, अमेरिका की 'पीवोट टू एशिया' से जोड़ने का वचन दे दिया। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत द्वारा चतुर्भुजीय सुरक्षा गठजोड़ कायम करने का मतलब इस बात की घोषणा करना है कि उसने घेरेबंदी की अमेरिकी रणनीति को अपना लिया है। ध्यान रहे कि जापान और आस्ट्रेलिया, अमेरिका के दो प्रमुख सैन्य गठबंधन सहयोगी हैं और अब ऐसा करके भारत स्वयं ही इस श्रेणी में आ गया। लेकिन भारत इन क्षेत्रों में लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा, जब गठबंधन और इसके सदस्यों का उद्देश्यों व लक्ष्यों के प्रति विचार समान एवं विज़न स्पष्ट हो। क्वैड का वास्तविक उद्देश्य है : मैरीटाइम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, इंडो-प्रशांत की तरह चीन के सरकने तथा बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव पर चीन को घेरने का या फिर एक साथ सभी मोर्चों पर आगे बढ़ने का।

इस प्रकार से देखें तो आरम्भ के दो वर्षों में एनडीए सरकार की विदेश नीति संबंधी पहलों ने भारतीय विदेश नीति को फास्ट ट्रैक पर ला दिया जो लंबे समय से 'स्टैंडबाइ मोड' पर थी। लेकिन फास्ट ट्रैक के अपने खतरे होते हैं। सबसे पहला खतरा तो यह होता है कि वे देश जो हमारे मित्र नहीं हैं या हमारे साथ प्रतिस्पर्धा में हैं अथवा जिनका व्यवहार हमारे हितों के प्रतिकूल हैं, उनमें हमारे प्रति आक्रामकता बढ़ती है और वे हमें प्रत्येक स्तर पर रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरा खतरा यह होता है कि फास्ट ट्रैक पर चलने के कारण कूटनीतिक विषयों पर बेहतर होम वर्क नहीं हो पाता इसलिए लाभांश संभावित होते हैं सुनिश्चित नहीं। तीसरा खतरा यह होता है कि फास्ट ट्रैक पर कनेक्टिविटी बेहतर होती है लेकिन केवल इससे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय

संबंधों में आए सुधार की समीक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि उसके परिणाम या उत्पन्न होने वाले प्रभावों की समीक्षा करनी होती है ताकि त्रुटियां सुधारी जा सकें, पर फास्ट ट्रैक पर चलने के कारण यह संभव नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ हमारी विदेश नीति के इस ट्रैक पर चलने के कारण हुआ भी, विशेषकर चीन की तरफ से।

चीन ने भारत के प्रति न केवल शंका प्रकट करना शुरू किया बल्कि उसने भारत के खिलाफ रणनीति बनानी भी शुरू कर दी। उसने भारत-चीन सीमा पर पीएलए को तो सक्रिय किया ही पिछले वर्ष भूटान के डोकालाम में ट्राइ-जंक्शन पर 73 दिनों तक युद्ध की संभावनाओं को बनाए रखे। हालांकि अभी 27-28 अप्रैल को प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति के साथ वुहान में अनौपचारिक शिखर बैठक हो चुकी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीन अपने दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडा को बदल देगा। उसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों को चेक डिप्लोमैसी के जरिए बीजिंग से कनेक्ट करना और भारत की शक्ति को काउंटर करना है। इसके परिणाम भी हमें दिखे। सबसे हाल का उदहारण मालदीव का है जिसने भारत को अंगूठा दिखा दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मालदीव के तानाशाही शासन को असली ताकत चीन से ही मिल रही थी। मालदीव प्रकरण में सबसे अखरने वाली बात तो यह रही कि मालदीव ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख की मालदीव यात्रा की मेजबानी की, भारत द्वारा तोहफे में दिए गए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को यह कहते हुए लौटा दिया कि पाकिस्तानी नौसेना उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी करने में समर्थ है।

भारत-नेपाल संबंधों में कुछ समय के लिए बड़ी खाई बनती दिखी। अप्रैल 2015 में नेपाल में जब भूकम्प आया था तब भारत ने उसे पूरी मदद पहुंचाई थी। लेकिन संविधान को लेकर चले मधेसी आंदोलन और बार्डर पर हुई नाकेबंदी के दौरान जब भारत से होने वाली आपूर्ति रुकी तो वहां बायकॉट इंडिया जैसे नारे सुने गये। नेपाली मीडिया प्राय: यह प्रचार करते हुए दिखती है कि उनके देश में मुद्रा-स्फीति भारतीय मुद्रा-स्फीति का परिणाम है। इसका एक कारण तो नेपाल का 'स्मॉल सिण्ड्रोम' या लैण्ड लॉक्ड सिण्ड्रोम हो सकता है जिसके चलते वह शंकालु तो रहता ही है साथ ही सौदेबाजी के अवसर भी तलाशता है।

अभी हाल में नेपाल यात्रा के दौरान भारत और नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण पहल की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल किसी परिभाषा से नहीं बल्कि उस भाषा से बंधे हैं जो भाषा विश्वास की है, रोटी-बेटी की है। हमारी प्रकृति भी एक है और संस्कृति भी, दृष्टि भी समान है और सृष्टि भी, चाह और राह भी समान है। नेपाल के बिना भारत की आस्था भी अधूरी है। दोनों देशों की दोस्ती किसी रणनीति या कूटनीति की मोहताज नहीं है। इस यात्रा के दौरान बिजली संयंत्र के शिलान्यास के साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से नेपाल के जनकपुर से भारत के अयोध्या तक बस यात्रा की शुरुआत कर परस्पर संबंधों को और घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया है।

अभी हाल में नेपाल यात्रा के दौरान भारत और नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण पहल की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल किसी परिभाषा से नहीं बल्कि उस भाषा से बंधे हैं जो भाषा विश्वास की है, रोटी-बेटी की है। हमारी प्रकृति भी एक है और संस्कृति भी, दृष्टि भी समान है और सृष्टि भी, चाह और राह भी समान है। नेपाल के बिना भारत की आस्था भी अधूरी है। दोनों देशों की दोस्ती किसी रणनीति या कूटनीति की मोहताज नहीं है। इस यात्रा के दौरान बिजली संयंत्र के शिलान्यास के साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से नेपाल के जनकपुर से भारत के अयोध्या तक बस यात्रा की शुरुआत कर परस्पर संबंधों को और घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया है।

मैथ्रीपाला सिरिसेना के बाद श्रीलंका से जो संबंध अच्छे हुए थे वे पुन: उदासीन हो गये हैं। हम्बनटोटा से लेकर कोलम्बो तक चीन के नियंत्रण में आता दिखायी दे रहा है जिसका वह धीरे-धीरे सैन्यीकरण करेगा। यह विदेश नीति के मुनरो सिद्धांत की अनदेखी है या फिर हमारी विवशता। बांग्लादेश के साथ जरूर बेहतर संयोजन बना जिसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 'नूतन प्रोजन्मो' की संज्ञा दी थी। बांग्लादेश के साथ संबंधों की मजबूती की दिशा में सबसे अहम पड़ाव रहा लैण्ड बॉर्डर एग्रीमेंट जिससे इस सीमा में आने वाली बस्तियों के लोगों को न केवल पहचान मिली बल्कि भारत के लिए इमीग्रेशन का खतरा भी कम हुआ। हालांकि तीस्ता जल विभाजन का सर्वसम्मत फार्मूला तय नहीं हो पाया, इसलिए बांग्लादेश के नगारिकों को शायद उस हद तक संतुष्टि न मिली हो जितनी कि मिलनी चाहिए। यह 2019 के चुनाव में अवामी लीग के लिए नुकसानदेह हो सकती है और अवामी लीग के कमजोर होने के अनुपात में ही वहां भारतीय पक्ष भी कमजोर होगा। इस दौरान भारत ने 'गेटवे ऑफ ईस्ट एशिया' के रूप में म्यांमार के महत्व को परखा और सांस्कृतिक साझेदारी का वातावरण भी निर्मित किया।

बहरहाल रक्षा रणनीति और भू-सामरिकता पर गौर करें तो भारत की स्थिति एक नाभिक की बनेगी और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि क्रोड राज्यों की श्रेणी में आएंगे। भारत की वास्तविक ताकत तभी प्रदर्शित हो पाएगी जब क्रोड राज्य अपने नाभिकीय राज्य के प्रति केंद्रीय बल से बंधे हों। भारत को इस भू-सामरिक गणित को अच्छी तरह से समझना होगा और इसी को केंद्र में रखकर विदेश नीति के विभिन्न आयामों को तैयार करने की कोशिश करनी होगी तभी भारत चीन की ताकत को काउंटर कर पाएगा, अमेरिकी कूटनीतिक व सामरिक जरूरतों के आकलन में प्रथम बिंदु पर पहुंच पाएगा, यूरोपीय देशों को आकर्षित कर पाएगा और मध्य व पूर्वी एशिया के बीच एक मजबूत सेतु की तरह स्थापित हो पाएगा। हालांकि इस दिशा में प्रगति हुई है लेकिन हमें भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक समीपता, समान भाषाएं, रीति-रिवाजों की सममितता, धार्मिक मान्यताओं, समीपता तथा भौतिक व सामाजिक संरचना में एकरूपता आदि का जो लाभांश हासिल करना चाहिए, वह अभी तक नहीं मिल पाया है। ❑